बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 192 ● नई दिल्ली ● शनिवार 16 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

डीडीए के किसी भी पार्क में सुबह 10 बजे तक एंट्री फ्री, एलजी संधू के निर्देश से कई लोगों को राहत

दिल्ली । दिल्ली में मॉर्निंग वॉक और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डीडीए के किसी भी पार्क में सुबह 10 बजे तक फ्री एंट्री मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर अब राजधानी के कई प्रमुख डीडीए पार्कों, ग्रीन एरिया और हेरिटेज साइट्स में एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। डीडीए के मुताबिक ये सुविधा खास तौर पर मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगर्स और फिटनेस गतिविधियों से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य यादा से यादा लोगों को खुले वातावरण में स्वास्थ्य और फिटनेस से जोड़ना है। जिन प्रमुख स्थलों पर सुबह 10 बजे तक एंट्री फीस माफ की गई है

राहुल के विदेश दौरों पर केंद्रीय मंत्री ने उठाया सवाल, कहा- संसद में बिना बताए करते हैं यात्रा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के यात्राओं पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिना सूचना दिए विदेश यात्रा करना गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद को अपनी यात्रा के बारे में 3 सप्ताह पहले सूचना देना अनिवार्य है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी की बिना सूचना के विदेश यात्रा गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रत्येक सांसद को अपनी विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को सूचित करना अनिवार्य है। यह अनुमति नहीं बल्कि सूचना है। सांसद विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सूचना देना आवश्यक है।

भारत से बाहर कितने दिन रहे?

अगर कोई सांसद विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करता है, तो उसे आमंत्रित करने वाली एजेंसियों या संगठनों द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च एफसीआरए के अंतर्गत आएगा। राहुल गांधी 2004 से सांसद हैं और उनकी 54 विदेश यात्राएं दर्ज की गई हैं। यह केवल 54 यात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि वे भारत से बाहर कितने दिन रहे और उन्होंने कितना खर्च किया।

विदेश यात्राएं क्यों की, जानकारी दे

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है कि वह नियमों का पालन करें और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी दें। उन्हें प्रस्तावित विदेश यात्रा से 3 सप्ताह पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करना होगा। अगर उन्हें विदेश में आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना है, तो उन्हें एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा। इसलिए, मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि वे स्पष्ट करें कि उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं क्यों की हैं।

देश के कानूनों का पालन करना चाहिए-रिजिजू

उन्होंने आगे कहा यात्रा करना उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि उन्हें किसने आमंत्रित किया है। भारत के बाहर की एजेंसियों/संगठनों ने उनके नाम पर क्या खर्च किए है? मेरा मानना है कि हर भारतीय को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। खासकर सांसदों को।

अगर कुछ होता है, तो कोई कार्रवाई शुरू की जाती है। राहुल गांधी या किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कानून सबके लिए है।

पहली बार दिल्ली में हाइड्रोजन बसें, जानें कहां से कहां तक चलेंगी, कितना होगा किराया?

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहली बार, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो को दो ऐसी अत्याधुनिक बसें सौंपी हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 15 मई यानी आज से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक एकीकृत हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू की। यह पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है। यह सेवा अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायक होगी। इन बसों में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग और सीसीटीवी प्रणाली लगी होगी। यह वास्तविक समय की निगरानी, सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। यह शटल सेवा सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर) में चलेगी। सेवा का समय सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा।

कनेक्टिविटी और मार्ग

यह सेवा सेंट्रल सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित प्रमुख सरकारी कार्यालयों को भी जोड़ना है। यह सरकारी अधिकारियों और आम जनता को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह सेवा कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर सड़क और बड़ौदा हाउस जैसे प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स और इंडिया गेट भी इस मार्ग में शामिल होंगे। डीएमआरसी बस संचालन, कंडक्टर, टिकटिंग और यात्री सहायता की जिम्मेदारी संभालेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ड्राइवरों की व्यवस्था करेगा। साथ ही वह हाइड्रोजन ईंधन सहायता भी उपलब्ध कराएगा। सेवा की फ्रीक्वेंसी हर 30 मिनट पर एक बस होगी। एक बस दक्षिणावर्त और दूसरी वामावर्त दिशा में चलेगी। किराया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, यूपीआई और नकद भुगतान के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें 10 रुपये और 15 रुपये की किफायती स्टेज आधारित टिकट दरें निर्धारित हैं। यह पहल भारत सरकार की हरित गतिशीलता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन ढांचे के प्रति सरकार के समर्पण का प्रतीक है। यह परियोजना भविष्य में पूरे देश में हाइड्रोजन आधारित परिवहन प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में देखी जा रही है। यह भारत के शहरी परिवहन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इसका लक्ष्य पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रदान करना है। यह पहल टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कुछ बेरोजगार युवा तिलचट्टों की तरह हैं, जो व्यवस्था पर हमले करते हैं, शीर्ष कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने शुक्रवार को कुछ बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे तिलचट्टों जैसे हैं, जो आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। यह टिप्पणी उस समय आई ,जब मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वकील ने वरिष्ठ वकील का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, पूरी दुनिया वरिष्ठ (वकील) बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं हैं। सीजेई ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वकील का पदनाम प्रदान करता

है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके पेशेवर आचरण को देखते हुए इसे रद्द कर देगा। सीजेआई ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, कई युवा तिलचट्टों की तरह हैं, जिन्हें न तो कोई नौकरी मिलती है और न ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं। कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसके खिलाफ कोई अन्य मुकदमा नहीं है। पीठ ने पूछा, क्या यह उस व्यक्ति का आचरण है जो वरिष्ठ वकील के रूप में नामित होना चाहता है? कोर्ट ने कहा, वरिष्ठ वकील का पदनाम एक ऐसी चीज है, जो किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है और इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या वरिष्ठ वकील का पदनाम एक प्रतिष्ठा प्रतीक है, जिसे केवल दिखावे के लिए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह उचित प्रतीत होता है? कोर्ट ने पाया कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कहना चाहता है कि वह काले कपड़े पहनने वाले कई लोगों की डिग्री सत्यापित करे, क्योंकि उनकी डिग्री के असली होने पर गंभीर शक है। पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें उनके वोटों की जरूरत है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। फिर पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

अब जेल में हर पार्सल पर नजर, एसओपी से बढ़ी जवाबदेही; जेल मुख्यालय ने जारी की नई मानक संचालन प्रक्रिया

नई दिल्ली । दिल्ली की जेलों में कैदियों को मिलने वाले पार्सल को लेकर अब जेल प्रशासन की मनमानी और प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं पर लगाम लगने जा रही है। जेल मुख्यालय ने नई मानक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। इसमें कहा कि पार्सल की जांच, रिकॉर्डिंग और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होगी। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब किसी भी पार्सल को बिना ठोस कारण के रोकना या उसमें देरी करना आसान नहीं होगा। जेल प्रशासन ने साफ कहा कि पार्सल से जुड़े हर फैसले का लिखित रिकॉर्ड रखा जाएगा। जेल के अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जेल में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कैदियों तक पार्सल पहुंचाने की प्रक्रिया में देरी होती है। कई मामलों में सुरक्षा जांच के नाम पर पार्सल लंबे समय तक लंबित रखे जाते थे, जिससे कैदियों और उनके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ती थी। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए जेल मुख्यालय की ओर से नई एसओपी लागू करने का फैसला लिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक जेल के उपाधीक्षक की मौजूदगी में पार्सल को खोलकर इसकी जांच होगी। पहले जेल के छोटे कर्मचारी इस काम को करते थे। इसके साथ ही जेल के वेलफेयर अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी है कि वह हर सप्ताह पार्सल रजिस्टर की जांच करेंगे। उन्हें यह भी देखना होगा कि किसी भी कैदी को उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर सुविधा से वंचित न किया जाए। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक पार्सल को सुरक्षा कारणों से रोकने पर जेल अधीक्षक को स्पष्ट कारण लिखित रूप से देना होगा। इसके साथ ही पार्सल में तंबाकू, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलती हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही पार्सल को एक्स-रे स्कैन कराया जाएगा। पार्सल में आने वाली सभी वस्तु एक रजिस्टर में दर्ज होगा। इससे सामान के गायब होने, बदलने या विवाद की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दिशा निर्देश में कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी।

सीएम योगी करेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास

गोरखपुर।

शनिवार (16 मई) की तिथि गोरखपुर की उपलब्धियों की श्रृंखला में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने जा रही है। खेल अवस्थापना सुविधाओं के लिहाज से गोरखपुर का नाम वैश्विक स्तर पर उल्लिखित कराने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों हेतु बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। करीब 393 करोड़ रुपये की लागत वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन की तरफ से ताल नदोर में उपलब्ध कराई गई जमीन पर 24 दिसंबर 2025 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। औपचारिक शिलान्यास होने से पूर्व, सरकार की तरफ से जारी परियोजना लागत की प्रथम किश्त 63.39 करोड़ रुपये से काम आगे बढ़ रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एक (भवन) के अनुसार अब तक करीब सात प्रतिशत काम हुआ है।

स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेशनल स्टेडियम के बन जाने से गोरखपुर आने वाले समय में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल के अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी जाना जाएगा। गोरखपुर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 46 एकड़ क्षेत्रफल में आकार लेगा। कुल 30 हजार दर्शक क्षमता का यह स्टेडियम 'ग्राउंड प्लस टू फ्लोर' के हिसाब से बनेगा। इसके मेन ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए 7 प्लेइंग पिच और 4 प्रैक्टिस पिच होगी। स्टेडियम के पूर्वी और पश्चिमी स्टैंड में प्रत्येक में 14,490 दर्शक बैठ सकेंगे। नार्थ पैवेलियन 208 वीआईपी व 382 मीडियाकर्मियों और साउथ पैवेलियन 1708 वीवीआईपी व वीआईपी के लिए होगा। रात्रिकालीन मैच भी हो सकें, इसके लिए मेन स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानक के चार हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था रहेगी। यहां क्रिकेट के अलावा अन्य बड़े आयोजन भी होंगे।

ताल नदोर में बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतरीन जगह पर है। गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग फोरलेन से जुड़ा यह स्थान, गोरखपुर एयरपोर्ट से करीब 24 किमी की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से करीब 20 किमी है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यहां पहुंचना काफी सुगम होगा। गोरखपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में देश की शीर्ष पेट्रोलियम कंपनियां अपने सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी) फंड से कुल 100 करोड़ रुपये देंगी। एमओयू के बाद धनराशि आवंटन प्रक्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण के लिए सीएसआर फंड से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60 करोड़ रुपये, भारत पेट्रोलियम 30 करोड़ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10 करोड़ रुपये देगी।

विमर्श के निहितार्थ

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय दिल्ली बैठक ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदेश दिए हैं, जिनके कूटनीतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। अन्यथा शेष दुनिया को अमेरिकी-यूरोपीय दादागिरी (नाटो सैन्य गठबंधन) के दुनियावी दांवपेंचों से निजात मिलनी मुश्किल है। लिहाजा, इस बैठक में मुख्य रूप से वैश्विक शक्ति-संतुलन, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर दिखाई दिया। देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल हैं। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है। इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नेताओं के दूरदर्शिता भरे बयान विशेष चर्चा में रहे। जिसके कूटनीतिक मायने बेहद अहम हैं। जिस तरह से कूटनीतिक सम्मेलन के पहले ही दिन जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका इशारा अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, ईरान मामले में भी गतिरोध की वजह बहुत हद तक वॉशिंगटन की अव्यवहारिक मांगें है। ब्रिक्स के बड़े मंच से उठी आवाज का असर बहुत दूर तक जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का उद्घाटन भाषण मौजूदा चुनौतियों का सही खाका खींचता है। पश्चिम एशिया पर मंडराता युद्ध का खतरा, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन में रुकावटें और जलवायु परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने का डर सता रहा है। ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, विकासशील देशों ने ब्रिक्स से यह उम्मीद लगाई है कि यह मंच स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। इसके कतिपय निहितार्थ इस प्रकार हैं- पहला, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती- बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह था कि दुनिया अब केवल अमेरिका-केन्द्रित व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ब्रिक्स देशों ने «मल्टीपोलर वर्ल्ड» के दृष्टिगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि वैश्विक निर्णयों में पश्चिमी देशों के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शक्तियों की भी बराबर भूमिका हो। दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का विरोध- भारत, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संप्रभुता के खिलाफ बताया। विशेष रूप से एस जयशंकर ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकते। यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना माना गया। तीसरा, डॉलर प्रभुत्व कम करने का संकेत बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। यह संदेश था कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिकी आर्थिक दबाव का असर घटाया जा सके। चतुर्थ, पश्चिम एशिया संकट पर चिंता- ईरान-इजराइल तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा। ब्रिक्स देशों ने रेड सी और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस मंच के सामने भी चुनौती है। ईरान और यूएई के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जबकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है। एक बात और, जब सम्मेलन की शुरुआत हुई, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तब ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त थे। ब्रिक्स के सबसे बड़े विरोधी ट्रंप हैं। उन्हें लगता है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा किया गया है। मेजबान होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी है कि यहां से निकला संदेश किसी के विरोध में नहीं, साझा हित में हो। भारत के पास सभी सदस्यों को करीब लाने और मौजूदा संकट का समाधान पेश करने का मौका है। पांचवां, ग्लोबल साउथ की राजनीतिक आवाज- बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स स्वयं को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि विकासशील देशों की सामूहिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्याओं—जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और कर्ज—को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता देने की बात कही गई। छठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग- भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दोहराई। यह संदेश था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं में अब नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होना चाहिए। सातवां, ब्रिक्स के भीतर मतभेद भी सामने आए- हालांकि बैठक में एकजुटता दिखाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य अमेरिका-विरोधी नीति पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और ईरान अधिक आक्रामक रुख चाहते हैं।

इससे यह संकेत मिला कि ब्रिक्स अभी पूर्ण राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि साझा हितों वाला मंच है। समग्र रूप से कहा जाए तो, इस बैठक का वैश्विक संदेश यह था कि उभरती शक्तियाँ अब विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्र, संतुलित और पश्चिम से अलग भूमिका चाहती हैं। ब्रिक्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि «ग्लोबल साउथ» अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। चूंकि ब्रिक्स अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा, इसकी भूमिका आज कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। वास्तव में यह वैश्विक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का रोल इसमें सबसे अहम हो जाता है। उसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, जबकि रूस, ईरान और चीन के साथ भी बैलेंस रखा है। उसने हमेशा संवाद से समाधान की बात की है। यह रवैया उसे भरोसेमंद साथी बनाता है।

ट्रम्प की चीन यात्रा का अर्थ

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वर्तमान में विश्व राजनीति में जो हड़कम्प मचा हुआ है उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को पुनः महान बनाने के चक्कर में पूरे विश्व क्रम को झिंझोड़ कर रख दिया है और यूरोप समेत समस्त एशिया व अफ्रीकी देशों के समक्ष आत्म सम्मान बचाने का संकट पैदा कर दिया है। भारत के पड़ोस ईरान में जो अमेरिका व इजराइल मिल कर ईरान के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं उससे विश्व के अधिसंख्य देशों के समक्ष ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति शेखी बघार रहे हैं कि अमेरिका के पास पैट्रोलियम तेल व गैस की कमी नहीं है। दरअसल यह अमेरिका की वह हठधर्मिता है जिसकी वजह से दुनिया के विकासशील एशियाई व अफ्रीकी देशों को अपने विकास के लिए कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। ऐसे विश्व वातावरण में ट्रम्प चीन की यात्रा पर हैं जहां वह इस देश के साथ अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में ट्रम्प चीन की यात्रा पर अपने राष्ट्रीय हित इस प्रकार साधने गये हैं कि चीन जैसा तेजी से विकास करता देश अमेरिका की सहायता के बिना कुछ न कर सके। मगर चीनी नेता भी बहुत तेज हैं और वे एशिया व अफ्रीका में अपने बढ़ते निवेश पर अमेरिकी नजर नहीं पड़ने देना चाहते। मगर यह भी सत्य है कि अमेरिका व चीन के बीच विश्वास की भारी कमी पैदा हो चुकी है जिसकी वजह से ट्रम्प कभी चीन पर भारी शुल्क दरें लगाने का ऐलान करते हैं तो कभी उसके साथ मतभेदों को दूर करने की तरकीबें ढूंढते हैं। चीन ने पिछले 15 वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर जो बढ़त प्राप्त की है उसकी वजह से अमेरिका व चीन की अर्थ व्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर होती जा रही हैं। एक तरफ चीन जहां दुनिया का उत्पादन केन्द्र बन चुका है और सामान्य उपभोक्ता सामग्री से लेकर टैक्नोलॉजी उत्पादन क्षेत्र तक में उसका दबदबा कायम हो चुका है वहीं अमेरिका उच्च टैक्नोलॉजी के क्षेत्र शोध व उन्नयन पर अपना कब्जा जमाये हुए हैं। अमेरिका की वरीयता है कि उसके बोइंग वायुयान से लेकर बीफ (मांस) सोयाबीन और बोर्ड ऑफ ट्रेड को संरक्षण मिले। बोर्ड ऑफ ट्रेड के माध्यम से अमेरिका सेमी कंडक्टर व कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर चीन को पछाड़े। अमेरिका चाहता है कि ऐसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाकर वह चीन के साथ अपने कारोबार में सन्तुलन लाये। क्योंकि चीन अमेरिका को जितना निर्यात करता है अमेरिका उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। दूसरी तरफ चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान के मामले में अपनी जिद छोड़े और उसे किसी प्रकार की मदद न दे। जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है तो चीन की कोशिश है कि अमेरिका उसके साथ उच्च टैक्नोलॉजी साझा करे और उसके आयात पर शुल्क की मुनासिब दर ही लागू करे। मगर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ईरान में चल रही लड़ाई भी है। ईरान के पक्ष में रूस व चीन इस प्रकार हैं कि वे हर कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान का समर्थन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का कोई भी वार निरुद्देश्य करते रहते हैं। हालांकि चीन प्रत्यक्ष रूप से ईरान की सैनिक मदद नहीं कर रहा है मगर उससे तेल की खरीदारी जारी रख कर वह उसकी अर्थ व्यवस्था को ढहने से बचाने का प्रयास भी कर रहा है। चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की सप्लाई करने में भी कंजूसी बरत रहा है जबकि इन पदार्थों का दुनिया में वह सबसे बड़ा वितरक है। इससे अमेरिका के वाणिज्यिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। अतः चीन व अमेरिका इस समय एक-दूसरे के साथ 'तू डाल-डाल मैं पात-पात' की तर्ज पर चल रहे हैं और सन्देश दे रहे हैं कि किसी एक की शर्त पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। इसका विश्व व्यवस्था के क्रम पर उल्टा असर पड़ रहा है क्योंकि पहले से बनी व्यवस्था के तहत बने नियामक इस प्रकार टूट रहे हैं कि कथित विकसित यूरोपीय देश व विकासशील एशियाई देश एक ही पंक्ति में खड़े नजर आने लगते हैं। यह संस्थागत तरीके से विश्व क्रम को उलटने का फार्मूला है जो ट्रम्प का इजाद किया हुआ है। अतः ट्रम्प व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेंट के बाद इस बात की संभावना ज्यादा है कि यदि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में और प्रगाढ़ता न भी आये तो स्थिरता जरूर आये। यह स्थिरता विश्व क्रम की स्थिरता के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है जिसके परिक्षेत्र में ईरान में चल रहा युद्ध भी आता है। चीन कूटनीतिक रूप से अमेरिका पर दबाव बना सकता है कि वह ईरान में स्थायी युद्ध विराम की घोषणा करे वरना चीन भी अमेरिका की भांति ताइवान को दी जा रही सैनिक मदद की तरह ईरान के पाले में खड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति भारत समेत विभिन्न अन्य देशों के लिए किसी भी तरह से प्रिय नहीं होगी क्योंकि तब युद्ध की विभीषिका नये तेवरों में प्रकट हो सकती है। अतः बहुत जरूरी है कि इन दोनों विश्व शक्तियों के बीच स्थिरता का वातावरण बने जिससे विश्व में बेचैनी और न बढ़े। मगर ट्रम्प के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नवम्बर महीने में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं और इस दौरान ट्रम्प की अपने देश में लोकप्रियता काफी घट गई है। अतः उनके लिए जरूरी है कि वह चीन से खाली हाथ न लौटें।

सम्पादकीय...

मजबूत आधारशिला

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उ0प्र0 डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हर कार्य कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन किये जा रहे है। आज के डिजिटल युग में सरकारी विभागों की बढ़ती ऑनलाइन सेवाओं, विशाल डाटा के सुरक्षित संरक्षण, विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन्स के केंद्रीकृत संचालन तथा नागरिकों तक त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं पहुंचाने की चुनौती लंबे समय से सामने रही है। अलग-अलग सर्वरों एवं बिखरी हुई तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण डाटा सुरक्षा, सेवा निरंतरता एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना कठिन हो रहा था। इसी चुनौती के समाधान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) की स्थापना की गई, जो आज राज्य की ई-गवर्नेन्स व्यवस्था का एक सशक्त और विश्वसनीय आधार बन गया है। यूपीएसडीसी के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों की जी-टू-सी तथा जी-टू-जी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केंद्रीकृत रूप से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे नागरिकों तक सेवाओं की त्वरित एवं पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश सरकार की नीति के तहत वर्तमान में लगभग 65 विभागों की 265 से अधिक विभिन्न एप्लीकेशन्स एवं वेबसाइट्स यूपीएसडीसी पर होस्टेड है। यह प्लेटफॉर्म विभागों की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विस्तार प्राप्त कर रहा है तथा विभिन्न विभागों को उनकी वेबसाइट एवं एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए आवश्यक स्पेस उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण ई-ऑफिस योजना भी यूपीएसडीसी पर सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिसके माध्यम से शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता और गति आई है। ई-ऑफिस प्रणाली ने सरकारी कार्यालयों में फाइलों के डिजिटल निस्तारण को बढ़ावा देते हुए पेपरलेस प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। डाटा सेन्टर की क्षमता वृद्धि एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तारीकरण का कार्य भी किए गए हैं। विस्तारीकरण के अंतर्गत नॉन-आईटी उपकरणों की स्थापना में 36 नवीन रैक्स लगाए गए हैं, जिनकी विद्युत भार क्षमता 14 किलोवाट से 21 किलोवाट तक है। इसके अतिरिक्त 2200 केवीए के 02 ट्रांसफार्मर, 1250 केवीए के 03 जेनसेट, 400 केवीए के 06 यूपीएस, एच.टी./एल.टी. पैनल सहित अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना कर यूपीएसडीसी को और अधिक सक्षम एवं सुरक्षित बनाया गया है। विस्तारीकरण योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान आईटी कम्पोनेन्ट्स के अंतर्गत अत्याधुनिक नेटवर्किंग उपकरणों, सर्वर एवं स्टोरेज सिस्टम की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य भी कराया गया है। इससे डाटा प्रोसेसिंग क्षमता, नेटवर्क सुरक्षा तथा एप्लीकेशन संचालन की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

देश की गोल्डन स्ट्रेटेजी

भारत में सोना केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की चीज है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहराते वैश्विक आर्थिक संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीयों से कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। सोना खरीदने का सीधा संबंध हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से होता है। भारत को सोने के हर एक औंस का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। सोने की जितनी ज्यादा खरीद उतनी डॉलर की मांग भी बढ़ती है और जितनी मांग बढ़ती है, उतनी डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। भारत सरकार ने भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दो दशकों में भारत ने लगातार अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ाई है। दूसरी तरफ भारतीय परिवारों के लिए सोना न केवल पारंपरिक गहनों के रूप में एक फैशन है, बल्कि यह समृद्धि, सुरक्षा और मुद्रास्फीति के खिलाफ एक दीर्घकालिक रक्षा के रूप में भी कार्य करता है। अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (450 लाख करोड़) के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी, 370 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। 'यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था में सोने के सांस्कृतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है।' आमतौर पर माना जाता है कि जब किसी संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो लोग खुद को अमीर महसूस करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं। इसे वैल्थ इफेक्ट यानी धन का प्रभाव कहते हैं। भारत में 75-80 प्रतिशत सोना ज्वेलरी के रूप में है। लोग इसे लॉन्ग टर्म सेविंग और परंपरा की तरह देखते हैं। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच सोना फिर से मजबूत और सुरक्षित निवेश के रूप में उभर रहा है। भारत में इस रणनीति को संभालने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जिसने हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर दुनियाभर में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। तनाव की स्थिति इस कदर बिगड़ रही है कि अब भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तेज हो गया है। इसके लिए विदेशों में रखा भारत का सोना वापस लाया जा रहा है। वहीं आरबीआई की अक्तूबर 2025 से मार्च 2026 की रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास इस वक्त कुल 880.52 मीट्रिक टन सोना है। इसका लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा यानी करीब 680 टन अब देश में ही सुरक्षित रखा गया है। सिर्फ 6 महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 104.23 मीट्रिक टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। वहीं 197.67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास है, जबकि 2.8 टन जमा के रूप में है। फिलहाल के हालातों को देखते हुए वैश्विक जोखिम से खुद को बचाने के लिए भारत तेजी से ये कदम उठा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ छह महीने में ही 104.23 टन सोना देश में वापस लाया गया है। बता दें कि मार्च 2023 तक हमारा केवल 37 प्रतिशत सोना ही देश में था। ये तेजी बताती है कि भारत अब किसी भी तरह के बाहरी जोखिम को हल्के में नहीं ले रहा है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा अफगानिस्तान और रूस के रिजर्व फंड पर रोक लगाने जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंकों की नींद उड़ा दी है। दुनिया को यह समझ आ गया है कि दूसरे देशों में रखी संप्रभु संपत्ति पूरी तरह से राजनीतिक फैसलों से सुरक्षित नहीं है। आज के टूटते वैश्विक मौद्रिक तंत्र में अगर सोना आपके सीधे कब्जे में नहीं है तो वह वास्तव में आपका है ही नहीं। भारत का यह कदम एक तरह का 'स्ट्रैटेजिक इंश्योरेंस' है। संकट के समय तरलता (लिक्विडिटी) के लिए यह तभी काम आएगा जब यह हमारी अपनी पहुंच में होगा। ऐसे में भारत विदेशों में जमा अपना सोना तेजी से वापस ला रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देश भी विदेशी जोखिमों से बचने के लिए अपना सोना वापस मंगा रहे हैं। फ्रांस 2026 की शुरुआत में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व से 129 टन सोना वापस पेरिस ले आया। जर्मनी न्यूयॉर्क में रखे अपने 1,236 टन सोने की सुरक्षा को लेकर विचार कर रहा है। टूटती वैश्विक व्यवस्था के मौजूदा दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक मानने लगे हैं कि अगर सोना उनके पास नहीं है तो ये उनका सोना नहीं है। मौजूदा सोने के मूल्य पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को सालाना लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी 950 करोड़ रुपये के आसपास की कस्टडी फीस देनी पड़ती थी। ये पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। भारतीय फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सोना सीधे उपलब्ध होगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर इसे रुपये की कीमत के लिए या स्वैप के माध्यम से डॉलर जुटाने के लिए तत्काल इस्तेमाल कर सकेगा। आज से 35 साल पहले खाड़ी युद्ध के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते के आयात के बराबर भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा।

इसके लिए भारत के स्वर्ण भंडार से 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड ले जाना पड़ा जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड चार्टर्ड विमान से ये सोना भेजा गया था। उस वक्त भारत का सोने का भंडार केवल 333 टन था। यानी 20 प्रतिशत सोना गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, वही बैंक ऑफ इंग्लैंड, वही स्विट्जरलैंड, जहां भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा लेकिन 2026 में युद्ध के हालात में भी भारत विदेश से अपना सोना वापस ला रहा है। उसी बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल रहा है, जिसके पास सोना गिरवी रखने की मजबूरी आई थी। उस वक्त सिर्फ 1 अरब डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के आसपास है। यानी 700 गुना ज्यादा। 2026 में सोना वापस लाना भारत के लिए गर्व की बात है। इसीलिए हम इसे देश का गोल्डन डिसीजन कह रहे हैं।

पंजाब में धर्म परिवर्तन का मुद्दा क्यों उभारा जा रहा है?

संविधान के अनुच्छेद 19 से 25 में दी गई नागरिक स्वतंत्रता के तहत हर भारतीय नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या विश्वास को अपनाने का अधिकार है। किसी भी विकसित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म व्यक्ति का निजी मामला होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश की राजनीति में धर्म परिवर्तन का मुद्दा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। केंद्र में मौजूद सत्ताधारी भाजपा इस मुद्दे को उछालकर अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। भारत के 12 राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बन चुका है। इनमें से अधिकतर राज्य भाजपा शासित हैं। कई राज्यों में धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए इस कानून के तहत कड़ी सज़ाएं रखी गई हैं। धर्मांतरण विरोधी संगठनों द्वारा यह दावा किया जाता है कि दूसरे धर्म के प्रचारक उनके धर्म (बहुसंख्यक धर्म) के लोगों (खासतौर पर गरीब और दलित लोगों) को जबरदस्ती या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही सामने आती है। असल में धर्म परिवर्तन के कारण सामाजिक-आर्थिक असमानता, सदियों से चली आ रही जाति-पाति और छुआछूत की व्यवस्था (जिसके अंश अभी भी समाज में मौजूद हैं) में निहित हैं। धर्म परिवर्तन का विरोध करने वाले राजनीतिक और धार्मिक समूह अपने धर्म के दलित और हाशिये पर पड़े लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने की बजाय उनका शोषण करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। वे जाति-पाति को अपनी संस्कृति बताकर उसका महिमामंडन करते हैं और कई जगह दलितों के मंदिरों में प्रवेश का विरोध करते भी दिखाई देते हैं। ये लोग यह तो चाहते हैं कि हाशिये पर पड़े वर्ग उनके धर्म का हिस्सा बने रहें, लेकिन उनके लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने से इनकारी हैं। विरोध करने वाले खुद दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में लालच, दबाव और धोखे से शामिल करते हैं—इस तरह की खबरें भी मीडिया में आती रही हैं। जिसे बहुसंख्यक धर्म के नेता «पवित्र काम» और «घर वापसी» कहकर सही ठहराते हैं। 2016 में पत्रकार नेहा दीक्षित ने आउटलुक में छपी अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने लाया था कि हिंदुत्ववादी सोच वाले संगठन कैसे आदिवासी इलाकों से वहां की लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर देश के अलग-अलग राज्यों में चल रहे अपने कैंपों में ले जाकर उन्हें अपनी विचारधारा की शिक्षा देकर उनका «ब्रेनवॉश» कर रहे हैं। इस तरह के लोगों पर धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कानून के तहत कार्रवाई की कोई खबर सामने नहीं आई। अब पंजाब में भी यह मुद्दा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि ईसाई प्रचारकों द्वारा लालच देकर दलित, सिखों और हिंदुओं का जबरी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धार्मिक संगठनों के साथ राजनैतिक पार्टियाँ भी इस मुद्दे पर अपनी बयानबाजी करने लगी हैं। हाल के दिनों केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा में 'बदलाव' रैली में इस मुद्दे को बड़े उकसाऊ ढंग से उछालते हुए कहा कि भाजपा पंजाब में एक नए कानून के जरिए धर्मांतरण पर रोक लगाएगी। मुम्बई में एक और जगह गुरु तेग बहादुर जी के 350 वें शहीदी दिवस पर सिखों से अपनेपन का दिखावा कर धर्मांतरण विरोधी अपनी सियासी विचारधारा को शाह इस तरह पेश करते हैं, यह कहा जाता है रहा है कि पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया पर यदि किसी भी तरह के लालच के कारण धर्म परिवर्तन हो रहे हैं तो यह हमारे गुरुओं की शिक्षा का अपमान है। साल 2011 की जनगणना में पंजाब में ईसाइयों की जनसंख्या 1.5 प्रतिशत थी। स्वाभाविक है कि यह पहले से बढ़ी है, लेकिन कितनी बढ़ी है इसके सही आंकड़े नहीं हैं क्योंकि 2011 के बाद सरकारी जनगणना नहीं हुई। गैर-सरकारी स्तर पर इस संख्या के 15 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है, कुछ दावे इसको और भी ज्यादा बताते हैं लेकिन यह तथ्य वास्तविकता से मेल खाते नहीं दिखते। पंजाब में चर्चों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, खासकर दोआबा और माझा क्षेत्र में, जो पारंपरिक कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्चों से अलग पादरियों द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाए जाते हैं। ऐसे चर्च में हर हफ्ते लोगों का एकत्र होना होता है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों, खासकर गुरदासपुर और अमृतसर के कई गांवों में गिरजाघर बन गए हैं, जिनमें दलित समुदाय के वाल्मीकि और मजहबी सिख अधिक जाते हैं। इन चर्चों को चलाने वाले अधिकतर धार्मिक गुरु तथाकथित उच्च जातियों से हैं। पेंडू मजदूर यूनियन के अध्यक्ष तरसेम पीटर बताते हैं, धर्मांतरण के मामले में विचार करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे को चुनाव के समय ही क्यों उभारा जाता है। पंजाब में अभी तक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का एक भी मामला सामने नहीं आया, न कोई पर्चा दर्ज हुआ है। अपनी मर्जी से किसी को भी किसी धर्म को अपनाने का हक है। पीटर कहते हैं, «असल में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की तरह पंजाब में भी सिखों को जबाती तौर पर उकसा कर सिखों और ईसाईयों (खास कर दलितों) को आपस में लड़वाना चाहती है और अपना राजनीतिक मकसद हासिल करना चाहती है। यह पंजाब में वैसे तो जीत हासिल करने योग्य नहीं है पर लोगों को धर्म-जाति के नाम पर लड़वाकर और दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर पंजाब में राज करने की सोच रही है। तरसेम पीटर बातचीत में हमें बताते हैं, भाजपा दलितों को भी आपस में लड़वाने का काम कर रही है। जैसे बाल्मीकी और रविदासी को, मजहबी और रामदासी भाईचारे को। पहले ईसाई मिशनरियों को अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आती थी, लेकिन केंद्र सरकार की रोक के बाद कुछ पादरियों ने स्वतंत्र संस्थाएं शुरू कर दीं। जैसे पंजाब में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, बरजिंदर देओल मिनिस्ट्री आदि शामिल हैं। यहां समाज के कमजोर वर्गों से आये लोग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने धर्म में इज्जत नहीं मिलती, जाति भेद-भाव सहना पड़ता है। एक तरफ तो भाजपा सिख समुदाय को इन संस्थाओं के विरुद्ध भड़काती है दूसरी तरफ भाजपा के कई दलित राजनीति करने वाले नेता भी इन संस्थाओं में जाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको पंजाबी में यीशु मसीह की भक्ति से जुड़े कई भजन और गीत मिल जाएंगे, जिन्हें गाने वाले भी सामान्य दलित परिवारों से हैं। कुछ दलित कलाकार ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन चर्चों ने उनकी कला को सही दिशा दिखाई और उन्हें पहचान दी है। इन ईसाई सभाओं में गाने वाले दीपक जोहनसन अपना अनुभव कुछ इस तरह साझा करते हैं, मैं एक गायक बनना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने प्रभु के लिए गायक बनूंगा। यहां जाने वाले दलित श्रद्धालुओं का कहना है कि इन चर्चों में उनका मानसिक और शारीरिक उपचार होता है। ईसाई धर्म गुरुओं द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में उनके बच्चों को मुफ्त या बहुत कम फीस पर अच्छी शिक्षा मिलती है। श्रद्धालु यह भी कहते हैं कि जो सम्मान उन्हें अपने पुराने धर्म में नहीं मिलता, वह उन्हें यहां मिलता है। यह बातें हमें तरन तारन जिला के कुछ दलित ईसाई श्रद्धालुओं ने बताई। ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित जनगणना आदि में अपना पुराना धर्म ही लिखवाते हैं ताकि उन्हें मिलने वाली आरक्षण की सुविधा समाप्त न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उन्हें और भी निराश करने वाला है। चर्चों में जाने वालों में बड़ी संख्या में पगड़ीधारी लोग मिल जाएंगे। कई ऐसे भी हैं जो अपने पुराने धर्म के कर्मकांड या पाठ-पूजा भी करते रहते हैं और पादरी द्वारा 'यीशु मसीह का दिया मंत्र या पाठ' भी दोहराते हैं।

इसी कारण पंजाब के कई विद्वान इसे धर्म परिवर्तन की बजाय डेरावाद की तरह देखते हैं, जहां लोग डेरा प्रमुख (संत) को भी अपने दुखों से मुक्ति की आशा में मानते हैं और अपने पुराने धर्म से भी जुड़े रहते हैं। माझा इलाके के कई दलित घरों में आपको सिख गुरुओं के साथ-साथ यीशु मसीह की तस्वीर भी मिल जाएगी। धर्म परिवर्तन करने वाले दलित यह तर्क देते हैं कि उनके पुराने धर्म में उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। उच्च सिख समूहों द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने का वे विरोध करते हुए कहते हैं कि अन्य लोगों की तरह उन्हें भी अपनी इच्छा से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। किसी को यह अधिकार नहीं कि वह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा डाले। वे यह भी मांग उठा रहे हैं कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी उनका आरक्षण का अधिकार बना रहना चाहिए। सीमावर्ती इलाके में कब्रिस्तानों के लिए जमीन का मुद्दा इन ईसाई अनुयायियों का मुख्य मुद्दा है। पंजाब में दलितों की आबादी 32 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 37 प्रतिशत तक चली जाती है। दोआबा क्षेत्र के कई इलाकों में यह आबादी 45 से 50 प्रतिशत तक चली जाती है, लेकिन दलितों का समग्र वोट बैंक कभी भी एक तरफ नहीं जाता। इसके कई कारण हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कमल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

तहसील फरेंदा में भूमि विवादों के खात्मे की तैयारी- खाली खेतों में टीम चलाएगी विशेष अभियान

महराजगंज।

ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों से चले आ रहे भूमि विवादों के स्थाई समाधान और सरकारी जमीनों को भू-माफियाओं से मुक्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेन्द्र गौतम ने कमर कस ली है।

तहसील फरेंदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त राजस्व कर्मियों, लेखपालों और कानूनगो को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे पूरे मनोयोग और निष्पक्षता से कार्य करते हुए हर गांव को भूमि विवाद मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करें। प्रशासन का मुख्य फोकस इस समय खाली पड़े खेतों का लाभ उठाकर सीमा संबंधी (मेड़बंदी) विवादों को तत्काल निपटाने पर है।

आपसी सहमति से सुलझेंगे मेड़बंदी के विवाद, पैमाइश के नाम पर नहीं लटकेंगे मामले

एसडीएम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सीमा संबंधी जिन मामलों को आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर सुलझाया जा सकता है, उन्हें बेवजह पैमाइश (नाप-जोख) के कानूनी वाद के नाम पर लंबे समय तक न लटकाया जाए। अक्सर देखा जाता है कि छोटे-मोटे मेड़ के विवाद कानूनी दांव-पेंच में फंसकर सालों-साल चलते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों बर्बाद होता है।

अब लेखपालों को गांव-गांव जाकर मौके पर ही दोनों पक्षों को बैठाकर बीच का रास्ता निकालने का निर्देश दिया गया है।

ग्राम सभा और भूमि प्रबंधन समिति की ली जाएगी मदद

एसडीएम ने शासनादेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि वे विवादों के निपटारे में गांव के निष्पक्ष व संभ्रांत नागरिकों तथा भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों का सहयोग लें। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में होने वाले फैसले अधिक व्यावहारिक और स्वीकार्य होते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीणों के बीच आपसी सौहार्द भी मजबूत होगा।

खेत खाली होने का सुनहरा मौका, कानूनगो करेंगे संवेदनशील मामलों की पहचान

एसडीएम ने कहा कि वर्तमान समय में रबी की फसल कटने के बाद अधिकांश खेत पूरी तरह से खाली हैं। प्रशासन का मानना है कि यह समय सीमा संबंधी विवादों को मौके पर जाकर हल करने के लिए सबसे उपयुक्त है।

सभी क्षेत्र के कानूनगो (राजस्व निरीक्षकों) को पाबंद किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों का दौरा करें, पुराने या सुलगते हुए विवादों की पहचान करें और प्राथमिकता के आधार पर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

गंभीर मामलों के लिए गठित होगी संयुक्त राजस्व टीम

उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र गौतम ने तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में विवाद की स्थिति गंभीर हो या शांति भंग होने की आशंका हो, वहां तत्काल प्रभाव से संयुक्त राजस्व टीम का गठन किया जाए। यह टीम मौके पर जाकर पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करेगी। किसी भी स्तर पर पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर कानून सम्मत अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा महा-अभियान; तय होगी जवाबदेही

एसडीएम ने बैठक में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों को भी कड़ा संदेश दिया गया है। तहसील के समस्त ग्रामों में सरकारी भूमि, चारागाह, पोखरे, खेल के मैदान और ग्राम समाज की जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर एक बड़ा अभियान चलाकर खाली कराया जाएगा।

तमकुहीराज में विवाहिता की संदिग्ध मौत, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका

कुशीनगर।

जनपद के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के शिवसरया बुजुर्ग गांव में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार 15 मई 2026 को सुबह करीब सात बजे डायल 112 को सूचना मिली कि ग्राम शिवसरया बुजुर्ग में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना मृतका के भतीजे सूरज शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम तुर्कपट्टी महुआ सूर्य मंदिर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज गिरजेश उपाध्याय तथा चौकी प्रभारी समउर अखिलेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अंजली शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा निवासी शिवसरया बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर, उम्र लगभग 30 वर्ष, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंजली शर्मा ने घर की छत पर लगे एंगल में दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजनों ने शव को नीचे उतारकर आंगन में रख दिया था। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार मृतका का व्यवहार सामान्य था, जिससे घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक तमकुहीराज गिरजेश उपाध्याय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

स्वर्णकार समाज ने जताई चिंता: रोजगार प्रभावित करने वाले फैसलों पर व्यापक चर्चा की मांग

रवि वर्मा

बृजेश वर्मा

अनिरुद्ध वर्मा

आनन्द वर्मा

दीपक वर्मा

भटनी बाजार।

स्वर्णकार समाज के लोगों ने झल के स्वर्ण कारोबार से जुड़े मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देशहित सर्वोपरि है, लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय से बचना चाहिए जिससे लाखों स्वर्णकार परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो। समाज के लोगों ने सरकार से स्पष्ट नीति और वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करने की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि यदि सोने की वैश्विक कमी की आशंका है तो बड़े स्तर पर होने वाले गोल्ड निवेश, आयात और कॉर्पोरेट कारोबार की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, न कि छोटे व्यापारियों और आम ग्राहकों को प्रभावित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार मुख्य रूप से पुराने आभूषणों के लेन-देन पर आधारित है, इसलिए छोटे ज्वेलर्स पर प्रभाव डालने वाले निर्णयों पर पुनर्विचार आवश्यक है।

*रवि वर्मा ने स्वर्ण व्यवसायी ने कहा कि देशहित सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे स्वर्णकार परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाए।

*बृजेश वर्मा, अध्यक्ष स्वर्ण शक्ति सोसायटी सोनार समाज, ने कहा कि व्यापार और रोजगार को प्रभावित करने वाले फैसलों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

*अनिरुद्ध वर्मा ने कहा कि सरकार को बड़े गोल्ड निवेश और आयात पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए, न कि छोटे व्यापारियों को प्रभावित करना चाहिए।

*आनंद वर्मा ने कहा कि स्थानीय बाजार पुराने आभूषणों के लेन-देन से चलता है, इसलिए छोटे ज्वेलर्स को राहत मिलनी चाहिए।

*दीपक वर्मा कारीगर ने कहा कि स्वर्णकार समाज हमेशा देशहित में खड़ा रहा है, लेकिन सरकार को समाज की आर्थिक सुरक्षा के लिए ठोस नीति और स्पष्ट रोडमैप भी देना चाहिए।

शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में गर्भस्थ शिशु के हृदय रोग का सफल उपचार, जन्म के बाद पूरी तरह स्वस्थ मिला बच्चा

गोरखपुर।

बाबा गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर अब आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रही है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में आयोजित एडवांस पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कैंप के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय रोग का सफल उपचार शुरू किया गया। जन्म के बाद लगातार निगरानी और आधुनिक जांचों के परिणामस्वरूप आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। पीपीगंज निवासी गर्भवती महिला प्रियंका सिंह के गर्भ में पल रहे शिशु की जांच के दौरान हृदय की मुख्य धमनी एओर्टिक आर्च में गंभीर समस्या का पता चला था। इस जानकारी के बाद परिजन अत्यंत चिंतित हो उठे। ऐसे कठिन समय में शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में उपलब्ध उन्नत सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श ने परिवार को नई आशा दी। मामले की देखरेख डॉ. नीरज अवस्थी ने की, जो स्कॉट फोर्टिस इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजी डायरेक्टर एवं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉ. अवस्थी वर्ष 2017 से प्रत्येक माह शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि नियमित निगरानी, समयबद्ध जांच और उचित उपचार से बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। जन्म के बाद बच्चे की प्रत्येक छह माह पर इकोकार्डियोग्राफी द्वारा जांच की गई। वर्तमान में बच्चा लगभग 18 माह का हो चुका है।

नवीनतम जांच में उसकी हृदय संबंधी समस्या लगभग पूरी तरह ठीक पाई गई है। यह सफलता न केवल परिजनों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि पूर्वांचल में बाल हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के अनुसार डॉ. नीरज अवस्थी के मार्गदर्शन में अब तक लगभग 650 बच्चों के हृदय का निःशुल्क ऑपरेशन सफलतापूर्वक कराया जा चुका है और सभी बच्चे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यह सेवा उन परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, जो बड़े शहरों में महंगा उपचार कराने में असमर्थ होते हैं। अस्पताल में अब लेजर तकनीक, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और उन्नत कार्डियक सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थानीय मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे गोरखपुर और आसपास के जिलों के मरीजों को बड़े महानगरों की ओर जाने की मजबूरी काफी हद तक कम हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से अब ब्रेन स्ट्रोक, फेफड़ों और किडनी की जटिल समस्याओं, अत्यधिक ब्लीडिंग तथा ऐसे कैंसर जिनका ऑपरेशन संभव नहीं होता, उनके उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। यह चिकित्सा व्यवस्था गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में गर्भस्थ शिशु के हृदय रोग की पहचान, समय रहते उपचार की शुरुआत और जन्म के बाद बच्चे का स्वस्थ होना यह साबित करता है कि सही समय पर जांच, विशेषज्ञ चिकित्सक और आधुनिक तकनीक मिलकर असंभव प्रतीत होने वाली स्थितियों को भी आशा में बदल सकते हैं।

एडवांस पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी कैंप ने गोरखपुर में आधुनिक चिकित्सा की नई उम्मीद जगाई

डॉ. नीरज अवस्थी की देखरेख में 18 माह तक नियमित जांच और उपचार से मिली बड़ी सफलता

पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में छोटे भाई को मार दी गोली,तीन महीने पहले हुई थी शादी

गोरखपुर। बेलीपार थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पत्नी से अवैध संबंध के शक में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। गोली गले में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दपुलिस के अनुसार, बेलीपार निवासी धर्मेंद्र पाल के पुत्र रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। गुरुवार रात करीब 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान रोशन पाल ने पिस्टल निकालकर छोटे भाई रोहन पाल पर फायर कर दिया। गोली रोहन के गले में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर डायल 112 और बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल रोहन को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से आरोपी रोशन पाल को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास अवैध असलहा कहां से आया। इस मामले में गांव के ही दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी रोशन पाल गांव की ही बिरादरी की युवती रुबी को भगाकर लाया था। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से करीब तीन माह पूर्व कौड़ीराम स्थित बगहा वीर बाबा मंदिर में दोनों की शादी कराई गई थी। परिवार में दो भाई रोशन और रोहन तथा एक बहन रोशनी है। घटना के समय घर में मौजूद पत्नी रुबी ने बताया कि वह और रोहन मिट्टी फेंक रहे थे। इसी दौरान रोशन वहां पहुंचा और आते ही पिस्टल निकालकर रोहन को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी रोशन पाल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

उन्नाव कांड - कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, 2 महीने में मुख्य याचिका पर फैसले का निर्देश

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही उच्च न्यायालय से याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय को यह भी निर्देश दिया कि वह सेंगर की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर मुख्य याचिका पर 2 महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करे। इसमें कहा गया कि यदि उच्च न्यायालय के लिए मुख्य याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेना संभव नहीं है तो उसे वहां ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले सेंगर की उस याचिका पर आदेश पारित करना चाहिए जिसमें मामले में आजीवन कारावास को निलंबित करने की मांग की गई है। पीठ ने इस मुद्दे पर भारी जन आक्रोश के बाद सेंगर को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को पहले ही रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और उच्च न्यायालय इस पर नए सिरे से सुनवाई कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय से ऐसे नए मुद्दों पर फैसला लेने को भी कहा कि क्या किसी विधायक को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के दौरान भी लोक सेवक माना जा सकता है। इससे पहले, न्यायालय ने बलात्कार मामले में पूर्व विधायक की आजीवन कारावास की सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई मई के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी थी। पिछले साल 29 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था, और कहा था कि उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 के अपने आदेश में कहा था कि सेंगर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (सी) (लोक सेवक द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन एक निर्वाचित प्रतिनिधि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है।

उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर के कारावास को उच्च न्यायालय ने उसकी अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था और कहा था कि पूर्व विधायक ने पहले ही 7 साल और 5 महीने की सजा काट ली है। उच्च न्यायालय के इस आदेश की समाज के विभिन्न वर्गों ने आलोचना की और पीड़िता, उसके परिवार और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया महंगाई मैन

नई दिल्ली ।

कांग्रेस पार्टी ने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये की बढ़ोतरी करके जनता पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में इस वृद्धि को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी की वसूली शुरू हो गई है।

महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया- कांग्रेस

कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज एक बार फिर जनता पर करारा प्रहार किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, सीएनजी की कीमतों में भी दो रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू।

पीएम मोदी पर कांग्रेस का करारा हमला

इसी के साथ कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक अलग पोस्ट में लिखा- अमेरिका में अदाणी पर चल रहा फ्रॉड का केस बंद हो जाएगा, अब साफ है कि मोदी ने अमेरिका के साथ एकतरफा डील इसलिए की ताकि अदाणी को राहत मिल सके। यही वजह है कि मोदी अमेरिका के आगे खुलकर बोल नहीं पाते है, ट्रंप जितना कहते है, मोदी उतना ही करते है।

विदेश यात्रा पर टैक्स की खबरों को पीएम मोदी ने बताया फर्जी, बोले- कोई प्रतिबंध या फैसला नहीं लिया गया

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी यात्रा पर टैक्स, सेस या सरचार्ज लगाने की खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी किसी भी योजना को लेकर सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पूरी तरह से झूठ है। इस तरह की खबरों में एक भी सच्चाई नहीं है और सरकार का फोकस आम लोगों के जीवन को आसान बनाने पर है।

कोई प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि ऐसी अफवाहें देश की नीतिगत दिशा को गलत तरीके से पेश करती हैं।

क्या था दावा?

एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि सरकार विदेशी यात्रा पर नया टैक्स या सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। दावा किया गया कि यह प्रस्ताव उच्च स्तर पर चर्चा में है और इसका उद्देश्य युद्ध संबंधी वित्तीय दबाव को संतुलित करना हो सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि यह संभावित शुल्क अस्थायी हो सकता है और इसका उपयोग इम्पोर्ट खर्च और कच्चे तेल की कीमतों के दबाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया संकट और देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से कुछ महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में छोटे-छोटे कदम भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि फिलहाल एक साल तक सोने की खरीद और दान से बचें, क्योंकि इसके आयात में देश का काफी विदेशी मुद्रा खर्च होता है। उनका कहना था कि इस तरह की बचत से देश के आर्थिक संसाधनों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने ईंधन बचत पर भी जोर देते हुए कहा कि अनावश्यक वाहन उपयोग को कम किया जाए, सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो का अधिक उपयोग किया जाए और कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे पेट्रोल-डीजल की खपत घटाई जा सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने खाद्य तेल की खपत को भी थोड़ा कम करने की सलाह दी।

भारत से संबंध बेहद अहम- अराघची

नई दिल्ली । ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत और ईरान के बीच मजबूत रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में बातचीत के दौरान उन्होंने भारत सरकार की मेहमाननवाजी की सराहना करते हुए कहा कि भारत के साथ संबंध ईरान के लिए बेहद अहम है। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अपना अच्छा मित्र बताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत संवाद का भी जिक्र किया। अब्बास अराघची ने कहा कि भारत सरकार और भारतीय प्रतिनिधियों ने उनके और उनके डेलिगेशन का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने खास तौर पर एस. जयशंकर के साथ अपने व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को मजबूत बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले दो महीनों के दौरान दोनों नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना रहा, खासकर उस समय जब उनके देश में संघर्ष की स्थिति थी। उन्होंने कहा कि जिस संघर्ष को दुनिया युद्ध कह रही है, उसे वह अपने देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई मानते हैं। इस दौरान भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत होती रही। भारत और ईरान के संबंध लंबे समय से ऐतिहासिक और आर्थिक साझेदारी पर आधारित रहे हैं। ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग देखने को मिलता रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, ईरानी विदेश मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब्बास अराघची ने अपने बयान में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जयशंकर के साथ उनकी व्यक्तिगत और कार्य संबंधी समझ काफी अच्छी है। दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करते रहे हैं।

बाबरी जैसी गलती दोहराई, भोजशाला फैसले पर ओवैसी का हमला; कहा- संविधान की मूल भावना की अनदेखी हुई

हैदराबाद । ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला मामले में आए फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि अदालत ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और पुराने दस्तावेजों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भविष्य में कई नए धार्मिक विवादों का रास्ता खोल सकता है।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक बना दिया गया

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद-राम मंदिर फैसले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, लेकिन अब उसी सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज जो फैसला आया है, उसने मेज ऑफ वर्शिप एक्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। अगर इस तरह फैसले आते रहे तो कल कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर दावा कर सकता है।

बाबरी मस्जिद फैसले से की तुलना

ओवैसी ने भोजशाला मामले की तुलना बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद से करते हुए कहा कि उस समय भी उन्होंने फैसले पर सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक, बाबरी फैसले में अदालत ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष का कब्जा लंबे समय तक बना हुआ था।

उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाबरी फैसले के बाद ऐसे कई मामले सामने आएंगे। उस समय लोगों ने मुझे चुप रहने को कहा था, लेकिन आज वही स्थिति सामने आ रही है।

वक्फ रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों का हवाला

ओवैसी ने दावा किया कि अदालत ने 1935 के धार स्टेट गजट और 1985 के वक्फ पंजीकरण को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि शीर्षक विवाद से जुड़ा सिविल मामला अभी भी लंबित है, इसके बावजूद इस तरह का फैसला दिया गया।

क्या है भोजशाला विवाद?

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार कोर्ट ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है।

यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया है। भोजशाला विवाद का नया कानूनी दौर 2022 में शुरू हुआ, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद

मार्च 2024 में एएसआई सर्वे का आदेश हुआ और 98 दिन तक जांच चली। जुलाई 2024 में रिपोर्ट पेश की गई। अप्रैल 2026 से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और जैन पक्षों ने अपने दावे रखे। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज, अमित शाह पर टिप्पणी और भड़काऊ बयानों के आरोप

नई दिल्ली । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए भड़काऊ और विवादित भाषणों को लेकर पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली है। यह मामला सीधे तौर पर चुनाव के दौरान माहौल खराब करने और देश के गृह मंत्री को धमकी देने के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। आरोप है कि इन रैलियों में उन्होंने बेहद आक्रामक और भड़काऊ भाषण दिए थे। इसी मामले में उनके खिलाफ

विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके भाषणों से समाज में नफरत फैल सकती थी और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती थी। इसके अलावा, उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे शब्द इस्तेमाल करने का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है।

शिकायत किसने दर्ज कराई?

टीएमसी नेता के खिलाफ यह अहम शिकायत राजीव सरकार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है। राजीव सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद यानी पांच मई को बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी बात साबित करने के लिए अभिषेक बनर्जी के कई विवादित भाषणों के वीडियो लिंक भी सबूत के तौर पर सौंपे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

पुलिस ने इस पूरी शिकायत की जांच करने के बाद 15 मई को दोपहर 2.45 बजे विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई सख्त धाराओं जैसे 192, 196, 351(2) और 353(1)(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 भी लगाई गई है। पुलिस की एफआईआर में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बहुत आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया था।

एफआईआर में क्या गंभीर बातें?

पुलिस की एफआईआर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभिषेक बनर्जी के भाषणों में ऐसी भड़काऊ और धमकी भरी बातें थीं, जो समाज में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने और सांप्रदायिक सौहार्द (भाईचारा) बिगाड़ने की क्षमता रखती थीं। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर सोमनाथ सिंह रॉय को सौंपी है।

आरजी कर केस पर एक्शन में शुभेंदु सरकार, 3 अधिकारियों पर गिरी गाज, नौकरी से सस्पेंड

बंगाल । आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले की शुरुआती जांच के दौरान कथित लापरवाही के आरोप में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित करने का आदेश दिया गया है. सीएम शुभेंदु ने कहा कि तीनों अधिकारी मामले को लापरवाहीपूर्ण तरीके से संभालने में कथित तौर पर शामिल थे. उन्होंने पीड़िता के माता-पिता को रिश्वत के रूप में पैसे की पेशकश की थी और अगस्त 2024 में हुए इस जघन्य अपराध के संबंध में एक अनाधिकृत प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया था. शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध की वास्तविक जांच में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच का नेतृत्व राज्य के गृह सचिव मुख्य सचिव के मार्गदर्शन में करेंगे.

पीड़िता की मां ने बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया

आरजी कर रेप-हत्या मामले में पीड़िता की मां और पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करना उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई का पहला निर्णायक कदम है. 9 अगस्त 2024 को अस्पताल में रेप के बाद देबनाथ की बेटी की हत्या कर दी गई थी. विधानसभा परिसर में देबनाथ ने कहा कि उनकी लड़ाई में एक अहम मोड़ तब आया जब वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हुई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शामिल होने राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचीं. उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद उनकी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. उन्होंने कहा, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस अपराध के दोषियों को सजा न मिल जाए और घर, कार्यस्थल या बाहर निकलने वाली हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस न करे और आरजी कर मामले समेत ऐसे सभी मामलों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न मिले.

नीट पेपर लीक में पुणे का केमेस्ट्री प्रोफेसर अरेस्ट - सीबीआई ने मास्टरमाइंड बताया; कोचिंग में छात्रों को सवाल बताए, नीट एग्जाम पैनल में भी रहा

नई दिल्ली । नीट (यूजी) पेपर लीक मामले में शुक्रवार को हुई गिरफ्तारी हुई। पुणे से केमेस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को सवाल और उनके सही जवाब बता दिए थे। CBI कुलकर्णी को ही लीक मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का डोमेन एक्सपर्ट है। कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहा है।

कुलकर्णी को पेपर तक सीधी पहुंच थी। वह पुणे में अपने घर पर कोचिंग क्लास चलाता था। जहां वो पहले से नीट पेपर में आने वाले सवालों का जवाब कैंडिडेट्स को बता देता था। 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई स्टूडेंट्स लीक पेपर दिया। इधर, पेपर लीक से दुखी दिल्ली की 20 साल की लड़की और यूपी के लखीमपुर खीरी के 21 साल के युवक और गोवा के 17 साल के लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है।

टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर हुआ था लीक पेपर

CBI की जांच में यह भी सामने आया है कि नीट 2026 का पेपर 1 मई को ही लीक कर दिया गया था। इसे प्राइवेट माफिया नाम के

टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया था। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। टेलीग्राम ग्रुप पर 1 मई की रात करीब 11:30 बजे डाले गए पेपर की PDF फाइल ओपन करने पर 12 नंबर का सेट दिखता है। इसकी पड़ताल करने के लिए हमने नीट के सेट नंबर-12 का पेपर निकाला।

CBI कुलकर्णी को ही लीक मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का डोमेन एक्सपर्ट हैं। कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहा है। कुलकर्णी को पेपर तक सीधी पहुंच थी। वह पुणे में अपने घर पर कोचिंग क्लास चलाता था।

लीक बताए पेपर और नीट के पेपर में एक जैसे सवाल

नीट के पेपर में सवाल नंबर 5 में एक बॉल के वर्टिकली ऊपर जाने और उसके वैक आने को लेकर वेलोसिटी और टाइम बताने के लिए फिगर बनाया गया है। ये सवाल लीक पेपर और असली पेपर में 100फीसदी मैच कर रहा है। इस पेज के दूसरे सवाल भी पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। नंबर-23 और 24 भी वही है, जो प्राइवेट माफिया के पेपर में है। यहां तक कि सवाल नंबर भी वही है। सवाल नंबर-23 में लिखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की किरण एक प्रिज्म ABC से गुजर रही है।

इस सवाल के साथ प्रिज्म की फोटो बनी है। लीक पेपर और असली पेपर में वही फोटो है। यहां तक कि सवाल के चारों ऑप्शन भी एक से हैं।

यानी ऑप्शन नंबर 1 में 40 डिग्री, ऑप्शन 2 में 45 डिग्री, ऑप्शन 3 में 55 डिग्री और ऑप्शन 4 में 35 डिग्री लिखा है। यही चारों ऑप्शन लीक हुए पेपर में भी हैं। इसके बाद सवाल नंबर-24 में जो मार्किट बनाया गया है, वही लीक पेपर और असली पेपर में भी है।

402 मेंबर का ग्रुप, पासवर्ड से लॉक

प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम ग्रुप में कुल 402 मेंबर हैं। इसे 2024 में ही पेपर लीक के लिए बनाया गया था। 1 मई को पेपर अपलोड करने से पहले एडमिन प्राइवेट माफिया ने मैसेज में लिखा था कि हम जल्द ही फुल पेपर अपलोड कर रहे हैं।

उसका पासवर्ड है LeakMafia@9466 है। इस मैसेज के कुछ देर बाद ही रात में करीब 11:38 बजे लीक पेपर ग्रुप में डाल दिया गया। इसके बाद दूसरा मैसेज लिखा गया- जो पेपर हमने भेजा है। उसे मॉल्व कर लो।

99.99 प्रतिशत चांस है कि यही पेपर में आएगा।